नीलम पुल की आग की कोई जांच नहीं, किसी की जवाबदेही नहीं

एमसीएफ के अधिकारी ने कहा- हम कहां-कहां चौकीदार बैठाएं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: नीलम पुल की आग तो बहुत पहले बुझ चुकी है लेकिन उसकी गरमाहट से फरीदाबाद की जनता के अभी भी पसीने छूट रहे हैं। एनआईटी इलाके में नीलम पुल के नीचे कबाड़ में आग 22 अक्टूबर को लगी थी। एक हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस आग लगने के जिम्मेदार नगर निगम के अफसरों-कर्मचारियों पर न तो कार्रवाई हुई और न ही किसी तरह की जांच का आदेश हुआ। नगर निगम को अब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही इस पुल को फिर से खोलने या उसके एक हिस्से पर ट्रैफिक आपरेशन चलाने पर विचार होगा। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी पर इस पुल पर ट्रैफिक नहीं शुरू कराना चाहता है।

जवाबदेही कौन तय करेगा

फरीदाबाद नगर निगम की ओर से नीलम पुल के नीचे आग लगने के मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इस संबंध में मजदूर मोर्चा ने एमसीएफ के सुपरिटेंडेंट ओ.पी. कर्दम से बात की। उनका कहना था कि वहां पड़े कबाड़ में आग लगी थी, एमसीएफ ने पुलिस में एफआईआर करा दी। इसमें नगर निगम के किसी अफसर या कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। यह पूछे जाने पर कि नगर निगम के संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने पुल के नीचे किसी कबाड़ी को कबाड़ कैसे जमा करने दिया, उनका कहना था कि नगर निगम हर जगह चौकीदार नहीं बैठा सकता। हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक बिल्डिंग इस्पेक्टर होता है। वह नजर रखता है। अकेला बिल्डिंग इंस्पेक्टर कहां-कहां नजर रख सकता है।

कर्दम ने बताया कि हमने नीलम पुल की रिपेयर और इसे फिर से शुरू करने को लेकर विशेषज्ञों की राय मांगी है। इसमें केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआईआई) के अलावा प्राइवेट एक्सपर्ट भी शामिल हैं। एमसीएफ भी चाहता है कि नीलम पुल जल्द से जल्द शुरू हो लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता है। इसलिए रिपोर्ट का इंतजार है। अगर विशेषज्ञ कहेंगे कि पुल का एक तरह का हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है तो हम फौरन खोल देंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या रिपोर्ट किसी निर्धारित समय सीमा में आयेगी, ओ.पी. कर्दम ने बताया कि विशेषज्ञ अपने समय के हिसाब से रिपोर्ट देंगे, हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते।

बहरहाल, जगदीश कबाड़ी को किस नगर निगम अफसर या कर्मचारी ने वहां कबाड़ जमा करने की छूट दी, एक गहन जांच से यह बात सामने आ सकती है। एमसीएफ की ओर से जगदीश कबाड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिस जगह कबाड़ में आग लगी, वहां इस कबाड़ी का गोदाम भी बताया जाता है। नगर निगम के अधिकारी इस पर चुप हैं। उसी जगह पर नगर निगम अपना कूड़ा भी डालता था, इस पर भी चुप्पी है। इस तरह एक बड़ी घटना पर रहस्यमय पर्दा पड़ा हुआ है।

परीक्षा की पहले से तैयारी नहीं

फरीदाबाद शहर को मथुरा रोड ने दो हिस्सों में बांट रखा है। उसके एक तरफ एनआईटी है तो दूसरी तरह सेक्टर्स हैं। दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए नीलम पुल के अलावा बाटा चौक पुल, ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास और बड़खल फ्लाईओवर हैं। हालांकि बडखल फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने की स्थिति में एनआईटी आने के लिए काफी घूम कर आना पड़ता है। आग लगने के बाद पुलिस ने न सिर्फ नीलम पुल बंद कर दिया, बल्कि उसके ऊपर से गुजरने वाले पैदल और साइकल सवारों का रास्ता भी रोक दिया है। इससे सारा जोर बाटा फ्लाईओवर, ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास और बडखल फ्लाईओवर पर पड़ रहा है। इससे सारे शहर का ट्रैफिक अस्तव्यस्त है। लोग कई किलोमीटर का चक्कर काटकर एनआईटी में अपने दफ्तरों और घरों को पहुंच रहे हैं। बाहर से आने वाले अनजान लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जब वे अजरौंदा मोड़ पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आगे बाटा फ्लाईओवर से जाना पड़ेगा। बाटा फ्लाईओवर पहुंचने पर जाम मिलता है।

इसी तरह ओल्ड फरीदाबाद चौराहे से रेलवे रोड पर बने अंडरपास के आगे और पीछे रेलवे स्टेशन के सामने रेहड़ियों की वजह से जाम की स्थिति हर वक्त बनी रहती है।

शहर में किसी पुल के नीचे आग लगने की यह पहली घटना है। आमतौर पर शहर का नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी ऐसी किसी आपदा की स्थिति में तैयारी का रोडमैप पहले से तैयार रखते हैं कि असामान्य परिस्थितियों में क्या करना है। लेकिन जब 22 अक्टूबर को पुल के नीचे आग लगी तो अफसरों और ट्रैफिक पुलिस के हाथ-पांव फूल गए।

अगर भविष्य में किसी भी पुल का कोई हिस्सा गिर जाए तब एमसीएफ और प्रशासन के आला अफसर क्या करेंगे, उस बारे में किसी भी तरह की योजना इनके पास नहीं है। उस दिन आग लगने पर फायर ब्रिगेड ने सबसे ज्यादा चुस्ती दिखाई। फायर ब्रिगेड के एडीएफओ आर. एस. दहिया और एनआईटी के फायर अफसर रमेश कुमार ने मौके पर फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां बुला लीं और आग पर काबू पाया।

क्या जिला प्रशासन और एमसीएफ भविष्य में मीडिया को इस बारे में बताएगा कि किसी असामान्य स्थिति में वह मथुरा रोड के दोनों तरफ बसे शहर को किस तरह जोड़ेगा और ट्रैफिक में बाधा नहीं आएगी।

रेहड़ी पटरी वालों का दर्द

नीलम पुल के नीचे आग लगने के बाद सबसे ज्यादा आफत किसी पर आई है तो वह बाटा चौक फ्लाईओवर के नीचे रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे-छोटे दुकानदार हैं। एमसीएफ के अधिकारी और कर्मचारी रोजाना यहां जाकर इनसे कह रहे हैं कि यहां से उन्हें हटना होगा। उन्हें हटाने की कार्रवाई नीलम पुल के नीचे लगी आग की आड़ में की जा रही है। हालांकि नीलम पुल की तरह बाटा फ्लाईओवर के नीचे किसी तरह की गन्दगी या कबाड़ा जमा नहीं है। रेहड़ी पटरी विकास संघ ने इस मामले को उठाया और एमसीएफ कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा।

संघ के अध्यक्ष दीन दयाल गौतम ने एमसीएफ के अफसरों को बताया कि बाटा चौक पर रेहड़ी पटरी दुकानदार पिछले 40 साल से बैठे हुए हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद चौटाला सरकार के समय करीब 350 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बाटा फ्लाईओवर के नीचे बैठने को कहा गया। उसके बाद से ये लोग वहीं बैठ रहे हैं। गौतम ने एमसीएफ अफसरों को बताया कि बाटा फ्लाईओवर की सुरक्षा हम लोग खुद कर रहे हैं। वहां बैठे तीन कबाड़ियों को हमने खुद हटा दिया है। इसी तरह टायर का काम करने वालों को भी फ्लाईओवर के नीचे से हटा दिया है। रेहड़ी पटरी विकास संघ का वादा है कि वो पुल के नीचे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं बिकने देंगे। दीनदयाल गौतम ने एमसीएफ से मांग की है कि जिस तरह नीलम पुल के नीचे नगर निगम ने दुकानें बना कर बेची हैं, ठीक उसी तरह बाटा फ्लाईओवर के नीचे हमें भी दुकानें आवंटित की जाएं। गौतम को एमसीएफ अफसरों ने आश्वासन दिया है कि अगर उनका संगठन जिम्मेदारी ले रहा है तो नगर निगम बाटा फ्लाईओवर के नीचे से छोटे गरीब दुकानदारों को नहीं हटाएगा।

बाटा फ्लाई ओवर रेहड़ी पटरी के प्रधान दीनदयाल गौतम ज्ञापन देते हुए

उधर, नीलम पुल के नीचे नाले के साथ बनी झुग्गियों को भी हटाने का आदेश नगर निगम ने दिया। उन झुग्गियों में बेहद गरीब परिवार रहते और किसी तरह शहर में मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। यहां रहने वाले कुछ लोग तो भीख तक मांगते हैं। ये लोग बहुत ही बुरे हालात में रह रहे हैं। यहां तो लाइट का इंतजाम है और न ही पानी का। नाले की गंदगी तमाम बीमारियों को वैसे भी जन्म दे रही है। लेकिन यहां लगी आग की वजह से यहां से इनका हटना तय है।

फ़रीदाबाद के मौजूदा ट्रैफ़िक जाम को ऐसे किया जा सकता है कम, ट्रैफ़िक पुलिस ध्यान दे

फ़रीदाबाद (म.मो.) **प्रशासनिक लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त हुए नीलम पुल के बंद होने से बाटा पुल, ओल्ड फ़रीदाबाद के अंडरपास पर ट्रैफ़िक का बढ जाना स्वाभाविक है। ऐसे में ट्रैफ़िक पुलिस यदि थोड़ा सा ध्यान दे तो समस्या से काफ़ी राहत मिल सकती है। बीते करीब पांच दिन स्थिति का अध्ययन करने पर पाया गया कि बाटा पुल या अंडरपास पर इतना जाम नहीं है जितना इन दोनों तक पहुंचने वाली सड़कों पर जाम लगा रहता है। हार्डवेयर चौक से बाटा पुल तक जाने के बीच सड़क पर दो कट हैं जिन पर वाहन दहने या बांये जाते हैं। पहला कट स्टील यार्ड के सामने है जहां से लम्बे-लम्बे ट्रॉले मुड़ते हैं; दूसरे, जब हाईवे की ओर से आने वाले वाहन पुल से उतर कर दहनी ओर जाते हैं तो वहां कुप्रबन्धन के चलते दोनों ओर का ट्रैफ़िक फंस कर खड़ा हो जाता है। यदि उसे ठीक से नियंत्रित किया जाये तो समस्या से काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा इस सड़क के दोनों ओर बड़े-बड़े ट्राले सड़क किनारे स्थाई तौर पर खड़े रह कर ट्रैफ़िक को बाधित किये रहते हैं। सड़क का इस्तेमाल पार्किंग की अपेक्षा यदि चलने मात्र के लिये रखा जाये तो काफ़ी राहत मिल सकती है।**

इसी तरह ओल्ड में अंडरपास तक जाने वाली दोनों ओर की सड़कों पर रेहड़ी वालों के अलावा पार्किंग द्वारा सड़क कब्जाने से अंडरपास तक पहुंचना व उसमें से निकलना काफ़ी कठिन हो जाता है। यदि दोनों ओर की सड़कों को कब्जा मुक्त करा दिया जाये तो आवागमन अपेक्षाकृत काफ़ी सरल हो सकता है।

खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

इंग्लैंड के पब ने वित्तमंत्री पर लगाया प्रतिबन्ध

इंग्लैंड के भारतीय मूल के वित्तमंत्री रिषी सुनाक पर उनके चुनाव क्षेत्र में स्थित एक बार व रेस्टोरेन्ट ने ताउम्र प्रतिबन्ध लगा दिया है। रिषी सुनाक व उनकी कन्जरवेटीव पार्टी के तीन एमपी, जो उस क्षेत्र से आते थे, उन्होंने स्कूली बच्चों को छुट्टियों में फ्री भोजन देने की योजना को बंद करने के पक्ष में मतदान किया था। इससे नाराज होकर रिषी के चुनाव क्षेत्र रिचमण्ड में नोर्थ योर्कशायर में स्थित 'द मिल' नामक पब व उससे जुड़े 'मुलिनो' रेस्टोरेन्ट ने यह प्रतिबन्ध लगाया। पब मालिक एलेक्स ने इसे बहुत बुरा फ़ैसला बताते हुए कहा कि वे तीन अलग-अलग भोजन बैंको को अगले हफ्ते से 100 खाने देने का प्रबन्ध करेंगे ताकि सरकार के निर्णय से बच्चों को हुये नुकसान की भरपाई की कुछ कोशिश कर सकें।

भारत से ज्यादा समृद्ध एक देश में बच्चों को मुफ़्त भोजन देने का लोग समर्थन करते हैं और उसे बंद करने पर सरकार के वित्तमंत्री तक पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में गरीब बच्चों को मिलने वाले 'मिड डे मील' का यहां यह कह कर विरोध किया जाता है कि आखिर हम कब तक अपने टैक्स के पैसे से इन मुफ्तखोरों को खाना खिलाते रहेंगे। और किसी रेस्टोरेन्ट द्वारा किसी मंत्री के घुसने पर प्रतिबंध लगाने की तो हिम्मत ही यहां किसमें है। हमारे और वहां के लोकतंत्र में यही फर्क है।

आरोग्य सेतु एप का रहस्य

एक आरटीआई के जवाब में सरकार के सभी विभागों मंत्रालयों ने आरोग्य सेतु एप के बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया। हालांकि 'एप' की वेबसाईट पर 'एनआईसी' और आईटी मन्त्रालय का नाम इसके कर्ता-धर्ताओं के रूप में दिया हुआ है लेकिन उन्होंने भी इस बारे में हाथ खड़े कर दिये। आरटीआई के जवाब में अन्य के अलावा इन दो मंत्रालयों/विभाग ने भी बताया है कि उन्हें नहीं पता ये एप किसने बनाया है और इससे प्राप्त होने वाली सूचना/डेटा किसके अधिकार क्षेत्र में है या किसके पास जमा है।

आरोग्य सेतु ऐप के लिये संसद में कोई कानून नहीं बनाया गया फिर भी एक सरकारी आदेश के जरिये इसे रेल, जहाज, होटलों अस्पतालों व अन्य अनेक जगहों पर जाने के लिये अनिवार्य बना दिया गया। बीजेपी और इसके लग्गे-भग्गों ने इसे कोरोना के खिलाफ़ एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया और जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे उनको बड़ा गरिआया था। इस तरह की सरकारी व गैर सरकारी धौंसपट्टी या मूर्ख बनाकर लगभग 15 करोड़ लोगों को ये एप 'डाउनलोड' करवा दिया गया। इसमें उनका निजी डेटा ले लिया गया और आज सरकार पल्ला झाड़ रही है कि उसे नहीं पता किसने इसे बनाया और इससे प्राप्त जानकारी किसके पास जमा है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने अगली सुनवाई पर सरकार के कई विभाग प्रमुखों को इस बारे में जवाब तलब करने के लिये बुलाया है।

बरोदा चुनाव में खिलाड़ियों में भी खेमेबंदी

बरोदा चुनाव में खिलाड़ी भी अलग खेमों में बंट गये हैं। जहां कुछ पहलवान कुश्ती खिलाड़ी भाजपा के योगेश्वर दत्त के पीछे खड़े है वहीं कबड्डी के खिलाड़ी कांग्रेस के इंदुराज नरवाल के पीछे घूम रहे हैं। ये खिलाड़ी कहीं रिले दौड़ से तो कहीं हाथ जोड़ कर अपने खेमे के लिये वोट मांग रहे हैं।

ये खिलाड़ी न अन्य खिलाड़ियों के लिये सुविधायें मांग रहे हैं और न सामाजिक कार्यों मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है कि वो सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये विभिन्न राजनीतिक खेमेबन्दियों में शामिल हो रहे हैं। राजनैतिक पार्टियां तो चाहती ही हैं कि इन शोशेबाजियों के सहारे ही चुनाव जीत लिया जाये। बाकी ये पब्लिक है सब समझती है।

अन्तिम मिसरा

दाढी बढाई थी टैगोर दिखने के लिये,
लोगों को दिखने लगे आसाराम, झांसाराम।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06